[Shri P.K. Kunjachen]

moving. The prices aiso have gone up. The price per kg. of rice in the countryside is about Rs. 8 / - or Rs. 9 / -. It is selling at eight or nine rupees per kilo! The people have got no work and they are not in a position to purchase rice. There is no work, there is no ration, and, as a result, deaths, starvation deaths, have occurred.

[TheVice-Chairman (Shri B. Satyanarayan Reddy) in the Chair]

I have got the details about those people who have died of starvation. But, due to paucity of time, I do not want to give the particulars. But, Sir, if you permit me, I would mention the names and other, particulars of those persons who have died.

Shri Ganghain Karbang, 55 years, died due to starvation, on the 15th January.

Bishnu Lakhmi Karbang, 25 years, died on the 21st January, due to starvation. Both of them belong to one family.

Rambarma Reang of Shurmun Village, Kalapani Panchayat, also died of starvation.

Ratan Mohan Tripura, aged 50, of Demchera Block died on the 9th February.

Kacha Krai Tripura, aged 35, also died on 12th February due to starvation.

All these have died of starvation and that is why I have given the particulars. I am prepared to give all the particulars and other details of these persons.

Sapta Lakhmi Tripura, aged 50, of Benang Rojapura, Chaomana Blot died on the same date.

One Kamburma Reang ot Sharmila Village, Kalapani Panchayat, Kaiichanpu-ra Block, North Tripura soid her chil

just Rs. 400/-! Now, the people are fleeing fiom Tripura and since it is in the

eastern part of the country, it is n^t easily reported. Everything is happening. People are going to Assam and other places, even to West Bengal, in search of work. A very seiious situation is developing.

Sir, if food materials are not immediately sent to Tripura, 1 do not know what .is going to happen there. You see, wticn the rains come, it is not possible to send the food materials there. If the rains come and food materials are not sent now- itself, then more starvation deaths will occur there.

I, thei efore, lequest the Covernment of lndia to see that immediately tood materials are sent there and also some anangements are made for giving work to the poor people, there.

With these words, 1 conclude my Special Mention. Thank you, Srr.

Government's Poiicy regarding modernin-sation of firearms

श्री शिव कुमार मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक सरकार का आदेश पहुंचा है सब जगह, जो आर्म्स लाइसेंसिज़ के होल्डर्स हैं उनके रिन्यूअल के बारे में। यह कहा गया है कि जिला स्तर के लिए जो लाइसेंस स्वीकृत हैं केवल उनका ही रिन्यूअल जिला मुख्यालय पर होगा और जो प्रदेश स्तर के लिए स्वीकृत है उनका रिन्यूअल प्रदेश की राजधानी में होगा और जिनकी स्वीकृति सारे भारत के लिए है उनका रिन्यूअल दिल्ली में होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस आदेश का समाचार लोगों तक पहुंचा तो उनको बड़ी परेशानी हुई है। सारे देश में लाखों लाइसेंसिज़ हैं, एक-एक जिले में हजारों-हज़ारों लाइसेंसिज़ हैं और उनमें से आधे तो ऐसे होंगे जो सारे हिन्दुस्तान के लिए अधीकृत हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हर आदमी दिल्ली में आकर' के

अपना रिन्यूअल कराएगा। होटलों में ठहरेगा, दौड़-धूप करेगा, खर्चा करेगा, इतना समय लगाएगा, परेशान होगा। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जो एस. डी. एम. कोर्ट हैं उनको तहसील मुख्यालय तक रहने के लिए आदेश दिए हैं। सर्किल का जो पुलिस अधीक्षक है उसको भी अपना निवास स्थान तहसील मुख्यालय पर इसीलिए करने का सरकार ने आदेश दिया है कि वहां पर जनता की तकलीफें, जनता की असुविधा, जनता की शिकायतें सुनने का उनको अवसर मिले और जनता को दूर न जाना पड़े। और जनता को दूर न जाना पड़े लेकिन यह हैरत की बात है कि बंदूक के, राइफल के या रिवाल्वर के लाइसेंस रिन्यूवल के लिए उनको दिल्ली आना पड़े या अपने सूबे की राजधानी में जाना पड़े। तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अनावश्यक है और जनता के लिए बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस आदेश को वापस ले और जिस तरीके से पहले इनके रिन्यूवल होते थे, उसी तरीके से रिन्यूवल तहसील और जिलों में कराए जाएं, धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): महोदय, यह सचमुच कष्ट की बात है कि सारे देश के लोगों को दिल्ली आना पड़ें या सूबे की राजधानी में आना पड़े देश में लाखों लाइसेंस है। इसलिए उनको काफी कठिनाई होगी। मैं इसे अपने आपको संबद्ध करता हूं और चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाए।

Increase in prices of hooks and notebooks

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान बढ़ते हुए कागज तथा छात्रों के लिए कापियों और किताबों के मंहगे होने की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार ने छात्रों को रियायती दर पर किताबें और कापियां दिलाने के लिए रियायती कागज देने की नीति बना रखी है। यह कागज मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों, परीक्षा की कापियों के लिए मुहैया कराया जाता है। यह काम सरकार पहले कागज मिलों पर लैवी लगाकर रियायती कागज संबंधित क्षेत्रों को अलाट करती थी, परन्तु सरकार ने 1987-88 में पेपर नियंत्रण आदेश वापस ले लिया। इसी आदेश के अंतर्गत कागज मिलों पर लैवी था। इसके बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से कागज दिलाना शुरू किया। सरकार इसके बदले हिन्दुस्तान पेपर मिल को 3 हजार रुपए प्रति टन की सबसिडी देती रही है। लेकिन पेपर नियंत्रण आदेश वापस लेने से जो शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार डेढ़ लाख टन से भी ज्यादा कागज अलाट करती थी, उस कागज की मात्रा घटाकर लगभग आधी यानि 80 हजार टन कर दी है। तब से बाजार में कापियों और किताबों के दाम बढ़ते जा रहे हैं।

दूसरी ओर इन कापियों को बनाने के लिए पूरे देश मे हजारों, लाखों श्रमिक कार्यरत थे। अब चूंकि इन उद्योगों को सही दाम पर कागज नहीं मिलता इसलिए एक तरफ ये उद्योग बंद हो रहे हैं और दूसरी ओर लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। महोदय, एक तरफ छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर छात्रों के प्रयोग में आने वाले कागज की मात्रा घटाकर आधी कर देना कहां तक न्यायसंगत है?

महोदय, एक तरफ सरकार रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की कई योजनाएं बना रही है और दूसरी तरफ इस नीति से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि कापियों को बनाने में महिलाएं भी काफी संख्या में लगी हुई हैं। इस नीति का कुप्रभाव कागज के ऐलाटमेंट को आधा करने से सभी लोगों पर पड़ रहा है। प्रधान मंत्री का कहना है कि हर किताब एक मशाल है और शिक्षा मंत्रालय इस मशाल को घटाकर आधा कर रहा है। तीसरी प्रभावशाली बात यह है कि सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यदि छात्रों को कापियों ठीक से न मिल पाएं तो हमारा यह आपरेशन ब्लैक बोर्ड आपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि नये वर्ष के बजट में सब्सिडी की राशि इतनी बढ़ाये जिससे कम से कम पेपर नियंत्रण आदेश के दौरान इतना कागज शिक्षा के क्षेत्र को मिलता रहे कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड सफल हो और लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद।

Need to formulate Afghanistan Policy

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, I rise to speak not about karnataka but something else. *(Interruptions)* I rise today to emphasise the need to define a new Afghanistan policy by the Government in view of the Changed circumstances in that country. Our past policy has been one of failure.